गणतंत्र दिवस सम्बोधन

प्रो. जगदीश मुखी

माननीय राज्यपाल, असम

के द्वारा

गुवाहाटी, 26 जनवरी, 2019

मेरे प्यारे असमवासियों,

मैं देश के ७० वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर असम एवं देश के समस्त नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ।

हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इतने बड़े देश में, जहाँ भाषा, पंथ, मान्यताओं और परम्पराओं की इतनी विविधता हो, वहाँ देश को एक सूत्र में बाँधती है हमारी आधारभूत सांस्कृतिक समरसता और हमारा संविधान। आज देश का हर नागरिक हर्ष और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहा है। आइए, इस शुभ अवसर पर हम अपने संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, जिनके ज्ञान, अनुभव, और दूरदृष्टि के कारण हम ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर पाए हैं जिसमें बिना भेद भाव के, बिना भय या पक्ष पात के, देश का हर नागरिक अपनी स्वतंत्र सत्ता को अनुभव करता है, अपनी आशा आकांक्षाओं को पूरा करने का यत्न करता है। इस शुभ दिन, हम आज़ादी के उन दीवानों का भी स्मरण करें, उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दें, जिनके अथक प्रयासों और बलिदानों से हमें हमारी स्वतंत्रता मिली। आज वह अवसर है जब हम फिर एक बार अपनी स्वतंत्रता, अपनी व्यवस्था, अपने संविधान का मूल्य जानें, उसके महत्व को स्वीकारें और अपनी समस्त शक्तियाँ देश को और समृद्ध एवं सशक्त करने में झोंक दें।

आज देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम विकास की नयी ऊँचाइयों को छू रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की एक अलग पहचान बन रही है और दुनिया भारत की तरफ़ आशा और विश्वास के साथ देख रही है। यह भारत एक नया भारत है, जिसके सपने बड़े हैं, हौसले बुलंद है, इरादे मज़बूत हैं- जो अपने अतीत के प्रति सजग तो है, और अपनी विरासत पर गर्व भी करता है, लेकिन जिसकी दृष्टि भविष्य पर टिकी है- एक स्वर्णिम, उज्ज्वल और गौरवशाली भविष्य पर- ऐसा भविष्य जो हम मिल कर रचेंगे- अपने श्रम से, अपनी प्रतिभा से, अपने विश्वास से।

देश का पूर्वोत्तर इस नए भारत को नयी गति देने वाला नया इंजिन है। प्रधानमंत्री जी इस बात को दोहराते हैं कि अगर देश को और तेज़ गति से विकास करना है तो देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर भाग को दोगुनी नहीं चौगुनी रफ़्तार से आगे बढ़ना होगा। इसलिए पूर्वोत्तर के विकास पर केंद्र सरकार ने विशेष बल दिया है, विशेषकर ढाँचागत विकास के क्षेत्र में। सड़कों और पुलों के निर्माण हों, नयी रेल लाइनों का जाल, वायु सेवा का विस्तार, या जलमार्ग का विकास- सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है।

पूर्वोत्तर में असम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है। यह विडम्बना ही है कि आज़ादी से पहले, असम के विकास का स्तर राष्ट्रीय औसत से ऊपर था। देश के विभाजन ने, इस प्रदेश को अलग थलग कर दिया- वाणिज्य और व्यापार पर जिसका ख़राब असर पड़ा और विकास की दौड़ में प्रदेश पिछड़ने लगा। जिस प्रदेश ने हमारी साझी

सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध बनाने में अग्रणी भूमिका निभायी थी, वही देश की मुख्य धारा से अपने आप को दूर और कटा हुआ पाने लगा। विकास की मुख्यधारा से दूर, अलगाववाद और उग्रवाद की त्रासदी को झेलते हुए हमारे प्रदेश ने बहुत कुछ सहा है। लेकिन अब आगे देखने का, आगे बढ़ने का समय है।

हमारा देश नया भारत है तो हमारा प्रदेश नया असम। हमारी सरकार भी, मोदी जी के संकल्प, 'सबका साथ, सबका विकास' को शासन की प्रेरणा मानते हुए, नए असम के निर्माण के लिए, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। पिछले कुछ दशकों के घाव अब दोबारा हरे नहीं होने दिए जाएँगे। हम एक जुट होकर प्रगति के नए अध्याय लिखेंगे और देश के अग्रणी राज्यों में अपनी विशिष्ट और चमकीली पहचान बनाएँगे। २५ दिसम्बर, २०१८ को देश के सबसे बड़े रेल और सड़क पुल, बोगिबील पुल को प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। यह सिर्फ़ नदी के दो तटों को नहीं जोड़ता, बल्कि विकास के नए आयाम को दर्शाता है। राज्य में नए राजमार्गों और पुलों का काम तेज़ी से हो रहा है। विकास की इस दौड़ में अब हम पीछे छूटने के लिए क़तई तैयार नहीं हैं।

भाइयों और बहनों, असम में अवैध घुसपैठ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए मेरी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है।जिस नए असम के निर्माण के लिए हम समर्पित हैं, उसमें अवैध विदेशियों के लिए कोई स्थान नहीं। इस राज्य के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का हक़ है और रहेगा। इसलिए हमने राष्ट्रीय नागरिक पंजिका का काम तेज़ी से आगे बढ़ाया और उच्चतम न्यायालय के निर्देशन और देखरेख में एक सटीक

और प्रामाणिक मसौदे को तैयार किया है, जिसमें राज्य के सम्पूर्ण प्रशासन तंत्र ने अपनी पूरी सामर्थ्य और निष्ठा के साथ योगदान दिया है। शुद्ध एवं प्रामाणिक NRC के लिए हम वचनबद्ध हैं और अपने अवैध विदेशी मुक्त असम के निर्माण के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

असम समझौते के अनुच्छेद ६ में, समझौते की आत्मा है। असम के मूल निवासियों के राजनैतिक अधिकारों को हर हाल में सुरक्षित रखा जाएगा। यह हर्ष और संतोष का विषय है कि इतने वर्षों बाद असम समझौते के अनुच्छेद ६ को संवैधानिक मान्यता मिलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो सभी सम्बंधित पहलुओं पर गहन विवेचना करके छह महीनों में अपनी रिपोर्ट दाख़िल करेगी, जिसके बाद संविधान में आवश्यक प्रावधान लाए जाएँगे, और वर्षों से अपेक्षित राज्य के लोगों की आकांक्षा पूरी होगी। विगत कई वर्षों से, या यूँ कहूँ कि दशकों से, असम की ६ जनगोष्ठियाँ -मोरान, मोटक, सूतिया, कोच-राजवंशी, ताई अहोम, चाय जनजाति-इस बात के लिए संघर्ष कर रही थीं कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की मान्यता दी जाए। हमने उनकी बात को समझा, उनकी पीड़ा को, उनके सपनो को समझा। इसलिए केंद्र सरकार ने यह फ़ैसला किया है कि इन सभी छह जनगोष्ठियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा करते हुए हम इस बात के लिए भी सचेत हैं कि मौजूदा अनुसूचित जनजातियों पर किसी तरह का दबाव और कुप्रभाव न पड़े। हम असम के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध हैं और साथ ही यहाँ के हर वर्ग की आशा आकांक्षा को पूरा करने के लिए भी पूरी तरह समर्पित हैं।

यह असम की अस्मिता को सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है।

क़ानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। असम ने उग्रवाद के दंश को वर्षों झेला है। हमारे ही भाई बहनों, बेटे, बेटियों को बरगला कर, उन्हें बंदूक़ उठाने के लिए उकसाया गया था। किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं हो सकता। लोकतन्त्र में बातचीत से बड़े से बड़े मसले हल किए जा सकते हैं। हमने उन सभी समूहों से बातचीत की पहल की है, बातचीत को आगे बढ़ाया है, जिनकी व्यवस्था में आस्था कम थी। हमें इसके सकारात्मक नतीजे मिल रहे हैं। १३ उग्रवादी संगठनों के साथ Suspension of Operation क़रारों को हमने अंजाम दिया है। अन्य संगठनों ने भी शांति प्रक्रिया में शामिल होने की सहमति दर्ज की है। उनकी जायज़ शिकायतों को दूर करने का हम हर सम्भव प्रयास करेंगे। कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व, बहकावे में या स्वार्थ में, देश को नुक़सान पहुँचाने के प्रयास करते रहते हैं। उन्हें उन विदेशी शक्तियों से मदद भी मिलती है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उनके प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती। आतंकवाद मुक्त असम का हमारा संकल्प अटल है। हम ऐसी किसी भी शक्ति का दमन और नियंत्रण करने में पूरी तरह समर्थ हैं। पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए सरकार नयी नयी योजनाएँ लेकर आ रही है। हमारी पुलिस और सक्षम बने, समर्थ हो, संवेदनशील हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं।

प्रशासनिक तंत्र को साफ़ सुथरा बनाना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार समाज की व्यवस्था को दीमक की तरह चाट कर, खोखला बना रहा है। सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता की बहुत

आवश्यकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो लोग बड़े पदों पर बैठें, उनकी चयन प्रक्रिया साफ़ सुथरी और पारदर्शी हो। असम लोक सेवा आयोग में और सुधार लाए जा रहे हैं। पहले जिस तरह से चयन प्रक्रिया में धाँधलियाँ हो रही थीं, उनका असर प्रशासनिक प्रणालियों पर पड़ा था। मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कठोर क़दम उठाते हुए, सरकारी नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी लाने का प्रयास किया है। साथ ही, उन सरकारी कर्मचारियों को 'कर्मश्री' पुरस्कार भी दिए, जिन्होंने सरकारी सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान दिया। मेरी सरकार ईमानदारी को समर्थन और प्रोत्साहन दे रही है, और दुर्नीति के विरुद्ध पूरी ताक़त से लड़ रही है।

भाइयों एवं बहनों, हम राज्य में विकास को नयी दिशा और गति दे रहे हैं। देश की 'ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी' को सार्थक ढंग से लागू करने में असम की विशेष भूमिका है। मेरी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। पिछले वर्ष ३, ४ फ़रवरी को आयोजित पहले निवेश सम्मेलन का सफल आयोजन करके हमने देश और दुनिया को यह संदेश दिया था कि यह बदला हुआ असम है, जो देश के कोने में स्थित नहीं बल्कि भारत और ASEAN के सम्बन्धों के केंद्र में है। हम इस बात को मानते हैं कि व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से हम अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत बना सकते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में हमें हमारी पहचान स्थापित करनी होगी। इसी कड़ी में, मेरी सरकार ने नागरिक उड्डयन मन्त्रालय के साथ मिलकर, उनके सहयोग से, UDAN (International) की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत गुवाहाटी से दक्षिण पूर्वी देशों की राजधानियों का हवाई सम्पर्क बनेगा। इस कड़ी में गुवाहाटी से ढाका और बैंकाक की

उड़ान जल्द ही शुरू होगी। गुवाहाटी airport के नए टर्मिनल की शुरुआत हो गयी है और इसका निर्माण कार्य अगले दो वर्षों में पूरा हो जाएगा। रूपसी में भी नए टर्मिनल का काम शुरू हो गया है। निकट भविष्य में जोरहाट और सिलचर में भी नए टर्मिनल बनाए जाएँगे और डिब्रूगढ़ airport का भी विस्तार किया जाएगा। गुवाहाटी airport से दुबई और होंगकोंग के लिए फलों और सब्ज़ियों का जाना शुरू हो गया है। इससे हमारे लिए एक बड़ा बाज़ार खुल गया है, जिसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा।

हमारे जलमार्ग हमारी आर्थिक प्रगति को और गंति प्रदान कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक हमारे लिए सिर्फ़ नदियाँ नहीं, हमारी जीवनरेखायें हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति को सींचा, उसे और समृद्ध बनाया और हमारी अर्थव्यवस्था को प्राणवान किया। इन नदियों के दोनों तटों पर जीवन अपने सम्पूर्ण सौंदर्य के साथ खिला है। इसलिए हमने इनकी सम्भावनाओं को उजागर करने के लिए और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, नमामि ब्रह्मपुत्र और नामामी बराक का आयोजन किया था। बांग्लादेश के साथ हुए समझौते के तहत हम जल्द ही चित्तगोंग बंदरगाह का वाणिज्य और व्यापार के लिए इस्तेमाल कर पाएँगे। इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग से हम अपने जलमार्गों का समुचित विकास करके, आने वाले वर्षों में, इस बड़े बदलाव का पूरा लाभ उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं।

मेरी सरकार एक ऐसे वातावरण को तैयार करने में लगी है, जिससे राज्य में निवेश आए, नए उद्योग लगें और लोगों को रोज़गार मिले। 'ईज़

आफ डूइंग बिज़नेस' में भी असम तेज़ी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। जहाँ उद्योग लगाने पर बल है, और उसके लिए आवश्यक नीतियों को लाया गया है, वहीं इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इन उद्योगों में संस्थापन पाने के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है, वो हमारे बच्चों में विकसित किया जाए। असम दक्षता विकास अभियान के माध्यम से इस वर्ष लगभग एक लाख बच्चों को दक्ष बनाने के लिए, प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दीन दयाल ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ३३२२९ ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया।

जहाँ एक तरफ़ कौशल विकास पर बल दिया जा रहा है, वहीं युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार हर सम्भव मदद दे रही है। Swami Vivekanand Assam Youth Empowerment एक ऐसी ही योजना है जो एक लाख युवाओं को उद्यमी बनाने में सहायक होगी। महिलाओं के लिए 'कनकलता महिला सबलीकरण योजना' के तहत १.१३ लाख Self Help समूहों को आर्थिक मदद पहुँचाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम हो रहा है। इसके साथ है राष्ट्र की मुख्य धारा में लौटे हुए उन युवकों और युवतियों को 'स्वावलम्बन' योजना के तहत मदद पहुँचायी जा रही है, जिन्होंने हथियार छोड़ कर औज़ार उठाये हैं।

मेरी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर विशेष बल दिया है। केंद्र सरकार की 'आयुष्मान योजना' स्वास्थ्य क्षेत्र में एक युगांतकारी पहल है। इस योजना को सफल ढंग से लागू करने के अतिरिक्त राज्य सरकार ने 'अटल अमृत अभियान' के माध्यम से आम जनता को मदद पहुँचायी है।

हम जानते है कि हर साल बीमारी की वजह से कितने परिवार ग़रीबी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जन मानस को सुरक्षा कवच प्रदान किया जाए। आयुष्मान भारत और अटल अमृत अभियान के माध्यम से हम असम की ९२% जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर पाने में समर्थ हैं। कैन्सर के इलाज और सुगम, प्रभावी एवं अफ़ॉर्डेबल बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट के साथ सरकार ने एक विशेष योजना साकार की है। इस योजना के लिए हमारी सरकार अगले दो सालों में १०८० करोड़ रुपए ख़र्च करेगी। इसके साथ इस क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट प्रदेश में ८३० करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस वर्ष हम तीन नए मेडिकल कॉलेजों का काम, नलबारी, कोकराझार और तिनसुकिया में प्रारम्भ कर रहे हैं।

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। शिक्षा आज गाँव गाँव तक पहुँच तो गयी है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने 'गुणोत्सव' का सफल आयोजन इस वर्ष भी किया। सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोग, मंत्री, विधायक, अधिकारी, सभी विद्यालयों में जाकर, शिक्षा के गुणात्मक स्तर को मापने और समझने का प्रयास करते हैं और अपनी उपस्थिति से विद्यार्थियों को प्रेरित भी करते हैं। इस योजना का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है और शिक्षा के केंद्रों के बीच स्वस्थ स्पर्धा दिखायी दे रही है, जिसके अच्छे परिणाम हमें आने वाले समय में अवश्य दिखायी देंगे।विद्यालयों के स्वरूप और सुविधाओं के सुधार के लिए २०१८-१९ के बजट में ९८० करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी, व्यावसायिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विकास के लिए भी हमनें इस वर्ष ६६७

करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मेरी सरकार प्रगति के नए आयाम स्थापित करना चाहती है। हम अपनी हर नीति, हर योजना, हर प्रकल्प से जन मानस के जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं। विश्व ने जिन महान आदर्शों के लिए सबको साथ आने के लिए आह्वान किया है, हम उनकी पूर्ति के लिए पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। इन आदर्शों को सही अर्थों में समाज में साकार करना हमारा लक्ष्य है। यह सरकार हर नागरिक की अपनी सरकार है। इसलिए सरकार के फ़ैसलों में, सरकार की योजनाओं में आपकी पूरी भागीदारी है। 'My Gov' के माध्यम से आपका सकारात्मक जुड़ाव हमें और शक्ति देता है।

" सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मक़सद नहीं
सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए "

मेरी सरकार उन तबक़ों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है, जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। सरकार ने 'प्रणाम' के माध्यम से सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अपने बड़े बुज़ुर्गों का भरण-पोषण करना, क़ानूनी बाध्यता कर दिया है। हमारा समाज स्वस्थ और भविष्योन्मुखी तभी हो सकता है जब हम अपने बड़ों और बच्चों का ध्यान रख सकें, उन्हें अपना स्नेह, सम्मान और सत्कार दे सकें। साथ ही दिव्यांगजनों के सम्मान और कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दीन दयाल दिव्यांग सहाय योजना के अंतर्गत इलाज के लिए १२००० रुपयों की आर्थिक सहायता प्रति वर्ष दिव्यांगजनों को दी जा रही है।

विकास तेज़ी से हो, इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता तो होगी ही। राज्य सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के हर सम्भव प्रयास कर रही है। साफ़ नीयत के साथ शासन करने से विकास भी सही होगा, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। पिछले वर्ष हमने राज्य के अपने संसाधनों में और वृद्धि की, जो प्रशासनिक तंत्र में आयी पारदर्शिता का नतीजा था। आबकारी, परिवहन और GST तथा अन्य प्रकार के राजस्व में रेकर्ड बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी। इसके साथ ही, हम ढाँचागत और सामाजिक विकास के लिए, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIB और NDB जैसी वित्तीय संस्थाओं से मदद लेने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे हम विकास को और गति दे सकें।

हम औद्योगिक विकास तो चाहते हैं, क्यूँकि बिना उद्योग और निवेश के रोज़गार का सृजन और सामाजिक उत्थान सम्भव नहीं। लेकिन हम पर्यावरण के प्रति भी पूरी तरह सचेत हैं। नया असम, प्रदूषण मुक्त भी होगा। इसलिए हम असम को और हरा, और निर्मल करने में लगे हुए हैं। ऐसे समय में जब किसी भी शहर और ख़ास तौर से हमारे बड़े शहरों में वायु प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है, ऐसे में असम की साफ़ हवा और निर्मल वातावरण लोगों को आकृष्ट करने में समर्थ है। आधुनिक जीवन शैली के कुप्रभावों से निजात पाने के लिए - खुली हवा में साँस लेने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए, जीवन और संस्कृति से जुड़ने के लिए, लोग असम आना पसंद करेंगे ही। इसलिए हम पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अपार सम्भावनाओं को पूरी तरह से उजागर करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। देश विदेश में, प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम अपनी पर्यटन सम्भावनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं और उन्हें

यहाँ आने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। प्रचार-प्रसार के अतिरिक्त हम पर्यटकों को और अधिक सुविधाएँ देने का प्रयास भी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं "खेलोगे तो खिलोगे"। भूपेनदा ने सही कहा है "यह पृथ्वी एक क्रीडाँगन है"। मुख्यमंत्रीजी ने गुवाहाटी को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प लिया है। मेरी सरकार इस दिशा में तेज़ी से काम कर रही है। खेल हमारी जीवन शैली को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करते हैं। शरीर में ऊर्जा, मन में उल्लास और खेल भावना का विकास, जिससे हम समूह में, समाज में, नियमों का पालन करते हुए, एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में तत्पर हों- ऐसा माहौल खेलों के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। राज्य में प्रथम पर्याय में पाँच सौ खेल मैदान तैयार करने का बीड़ा हमने उठाया है। खेलों की सुविधाएँ गाँव पंचायत स्तर पर देने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। एक ऐसे वातावरण की सृष्टि करना चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा खेल भावना से भरा हुआ हो और प्रदेश के विकास में अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ योगदान दे। इसी उद्देश्य से हम एक नयी क्रीड़ा नीति लेकर आए हैं, जिससे खेल सम्बंधी सुविधाओं को मुहैया कराने में आसानी होगी तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए आर्थिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाने वाले हमारे खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएँगे। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमने स्वर्ण कन्या हिमा दास को ट्रैक पर उड़ते देखा- उसके जुनून, उसके जज़्बे को देखा। हिमा दास, हृदय हज़ारिका, लवलीना बोरगोहाईं और उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपने प्रदर्शन से हमें रोमांचित भी किया और गौरवान्वित भी। इस राज्य में प्रतिभाओं का अभाव नहीं और अब उन्हें अभावों से

जूझना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार अपने हर हीरे को तराशने के लिए हर सम्भव काम करेगी। गुवाहाटी में अर्जुन भोगेश्वर बरुआ क्रीड़ा विद्यालय और छबुआ में अनिरुधदेव क्रीड़ा विश्वविद्यालय इसी दिशा में उठाए गए क़दम हैं, जो आने वाले दिनों में खेलों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

मेरी सरकार शहरों को नए ढंग से, वैज्ञानिक तरीक़े से विकसित करने पर बल दे रही है। हमारी शहरी योजनाएँ पहले आनन-फ़ानन में बनी हैं, जिसकी वजह से शहरों का विकास बेतरतीबी से हुआ है। स्टेट कैपिटल रीजन की योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसी ही समग्र योजनायें हम असम के अन्य महत्वपूर्ण शहरी इलाक़ों के लिए भी ला रहे हैं। हमारे नगर हमारी अर्थव्यवस्था को और मज़बूती प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यह तभी सम्भव है जब इन्हें सही ढंग से विकसित किया जाए। ग्रामीण विकास पर जो ज़ोर हमने दिया है वह जारी रहेगा। मुख्य मंत्री समग्र ग्राम उन्नयन योजना के माध्यम से हम ग्रामीण इलाक़ों को विकास की धुरी बनाकर, हमारे कृषकों की आय को दोगुना करने में तत्पर हैं। इसके लिए हमने अपने कृषक बंधुओं को ट्रेक्टर दिए हैं और आने वाले समय में कृषि के विकास के लिए, सिंचाई के लिए, कृषि उत्पाद के संरक्षण, उसकी सही मार्केटिंग के लिए, हम और भी बड़े और महत्वपूर्ण क़दम उठाने वाले हैं। हर गाँव समृद्ध हो, ख़ुशहाल हो- यही हमारा सपना है, यही हमारा संकल्प है। इसलिए गाँव स्तर पर हर उस सुविधा को उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके अभाव में, लोग शहरों की तरफ़ भागते हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण अंचलों में १,१६,०९१ घरों का निर्माण

कर लिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन प्रयासों से गाँव में जीवन का स्तर और बेहतर होगा।

केंद्र सरकार की उन सभी अभिलाषी योजनाओं को मेरी सरकार पूरी लगन और ईमानदारी के साथ लागू करने में जुटी है, जिनसे सामान्य जनमानस के जीवन में बदलाव आएगा- उसका जीवन और सरल, और सुंदर और सुखकर होगा। देश के सुदूर कोनों तक बिजली पहुँच गयी है। असम का भी हर गाँव रोशन हो गया है। अंधेरों का आधिपत्य समाप्त हो गया है। इसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत राज्य में गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिनसे हमारी माताएँ और बहनें धुएँ के प्रकोप से मुक्त हुई हैं। जन धन योजना के तहत सभी का बैंक खाता खुला है। चाय बाग़ानों में रह रहे हमारे चाय मज़दूर भाइयों और बहनों के भी बैंक खाते खोले गए हैं। ऐसे ७,२१,५८५ खातों में, २५०० रुपए प्रति खाते के हिसाब से राज्य सरकार ने हमारे चाय श्रमिकों को दिए हैं। जल्द ही इतनी ही राशि उनके खातों में और दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जाएगा।

इस वर्ष हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की १५० वीं जयंती मना रहे हैं। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान पर विशेष बल दिया जा रहा है। २८ ज़िले, २०४ ब्लाक, २४११ गाँव पंचायत, २२४१८ गाँव ODF घोषित कर दिए गए हैं और इस वर्ष २ अक्टूबर, २०१९ से पहले सम्पूर्ण राज्य ODF हो जाएगा।

हम एक नए युग की दहलीज़ पर खड़े हैं। खुला हुआ आसमान हमारे पंखों को चुनौती दे रहा है। चुनौतियाँ हैं, होनी भी चाहिए। संघर्ष है, होना भी चाहिए। लेकिन विश्वास हिलोरें मार रहा है, नए सपने कुलबुला रहे हैं। एक नया सवेरा हमारे इंतज़ार में थोड़ी दूर पर ही रुका हुआ है। ऐसे में हमें अपने पूर्वजों के उस आह्वान का स्मरण करना चाहिए कि देश के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह राष्ट्र का पुरोहित बनकर समूचे राष्ट्र को जागृत रखे। हम राष्ट्र के सजग प्रहरी बनें और देश के विकास में अपना पूरा योगदान दें।

"वयम् राष्ट्रे जागृयाम् पुरोहितः"

हमें हमारे सुंदर भविष्य के प्रति आशान्वित रहते हुए, और कठिन परिश्रम करना होगा। ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं, जो हम मिलकर प्राप्त नहीं कर सकते। इस अवसर पर अटल जी की ये पंक्तियाँ हमें नयी प्रेरणा देती हैं।

"आदमी को चाहिए कि वह जूझे
परिस्थितियों से लड़े,
एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े।"

आइए हम फिर से संकल्प लें, कि हम अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से अपने राज्य के विकास में समर्पित हों। हमें मिलकर असम को आगे ले जाना है। और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि असम का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। सारी बाधाओं को दूर करते हुए, लक्ष्य पर दृष्टि जमाए, हम पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। अब हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं और अपने

लक्ष्य से डिगेंगे भी नहीं। हमारा लक्ष्य है असम का विकास, तेज़ विकास, स्थायी विकास। इस अवसर पर रूपकुँवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला की ये पंक्तियाँ हमें और प्रेरणा देंगी।

"मये भारतर नवीन सूर्य
पूर्वांचलत बजाऊँ तूर्य
मोर पोहरर गाने-
आकाशे आकाशे, देशे, महादेशे
मुग्ध करिबो, आलोक यात्री
शेष हबो शेष नोहोवा रात्रि
करिम जगत जय
नवीन सूर्य मइ!"

जय हिंद।

***

2019

Printed at the Assam Government Press
Guwahati-21